निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	11900	मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाइन नस्ती/डाक प्रचालन	1. मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन का क्रियान्वयन (11770 अवकाशों का संपादन पूर्ण) 2. मंत्रायल के समस्त विभागों में ऑनलाइन अचल सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) (854 आई.पी.आर. का संपादन पूर्ण) 3. मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (901 ऐ.सी.आर.) का संपादन पूर्ण 4. 4 मंत्रायल के समस्त विभागों के लिए समय सीमा डाक एवं मीटिंग मोड्यूल का क्रियान्वयन	8330	
2.	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट योजना	ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाना	33800	विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	वर्तमान में समस्त विभागों को एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के अंतर्गत ऑन बोर्ड किया जा चुका है, जिसमें शासकीय निविदाओं का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 92254 करोड़ रू. की लगभग 38000 से अधिक निविदा प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है एवं 13292 ठेकेदारों को ऑन-बोर्ड किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 13200 से अधिक ठेकेदारों सक्रिय है।	28000	
3.	मुख्यमंत्री डैशबोर्ड याजना	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	12622	कृषि, स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास तथा जल	परियोजना अंतर्गत सलाहकार सेवा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय को सलाहकार सेवा प्रदाय की गयी । प्रदेश स्तर पर विभागों व योजनाओ की जानकारी	5409	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				संसाधन विभाग की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का विकास एवं संचालन	सम्बन्ध में डैशबोर्ड का मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नियमित उपयोग किया गया ।		
4.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	210000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	3 निवेश प्रस्तावो को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनका कुल प्रस्तावित निवेश रु 17.68 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 279 है । दिसम्बर 2018 के अनुसार इन्वेस्टर स्टेटस रिपोर्ट अनुसार, 13 अनुमोदित निवेशकों ने रुपये 50.32 करोड़ के निवेश तथा 1976 को रोजगार प्रदान करने की सूचना दी है । 2018 में निवेश आवेदनो से कुल रुपये 9.2 लाख आवेदन प्रसंस्करण शुल्क प्राप्त हुए है 9 निवेश प्रस्तावो प्राप्त हुए है जिनका कुल प्रस्तावित निवेश रु 41.08 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 2,059 है। इसके अंतर्गत 8 निवेश प्रस्ताव, जिनका कुल प्रस्तावित निवेश रु 39.38 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 2,049 है, को अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है	69400	
5.	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	277959	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	राज्य के जिला, तहसील एवं विभागों में कुल 2101 स्थानों पर स्वान से उपलब्ध कराई गई कनेक्टिविटी का संचालन एवं संधारण किया गया है ।	11184	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	59759	विभागों को जी.2सी. नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करना	विभिन्न विभागों की 126 ऑनलाईन सेवाएँ लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2018-19 में लगभग 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 24.46 लाख आवेदन निरोंत किये गए हैं।	0	
7.	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना	25730	एक सशक्त इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर की स्थापना	1. लाभान्वित स्टार्टअप की संख्या 102 8 स्टार्टअप कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम कर रहे हैं 9 स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं 12 स्टार्टअप शिक्षा में काम कर रहे हैं 17 स्टार्टअप साफ्टवेयर उद्योग में काम कर रहे हैं और अन्य उद्योग से 56 स्टार्टअप में से एक भारत में 3 डी प्रिंटर निर्माता अग्रणी है। 2. अंतर्राष्ट्रीय सहकार्यता 4 उज्बेकिस्तान, फिनलैंड, इजराइल, अमेरिका 3. घरेलू सहकार्यता 10 Google इंडिया, अमेजॅन आदि 4. 36Inc छत्तीसगढ़ के 20 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने कालेज परिसर में इनक्यूबेटर को स्थापित करने के लिए मदद कर रहा है	6400	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8

5. ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप विकसित करने के लिए, 36Inc सामाजिक उद्यमियों का बैच चला रहा है। इस के पहले बैच ने 24 जून को इसे पूरा किया। अमेरिकी सरकार द्वारा इन प्रयासों को मान्यता दी गयी और स्नातक समारोह में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और प्रमुख पीसटेक लैब, यूएसए द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है।

6. इंजीनियर्स, मैनेजर्स, CA के विभिन्न स्ट्रीम के कई प्रोफेशनल, जो दूसरे राज्यों में पलायित थे वे 36Inc इनक्यूबेटेड स्टार्टअप में शामिल होने के लिए वापस लौटे । 36Inc की उपस्थिति के कारण मूल छत्तीसगढ़ के निवासी जो मेट्रो शहरों में व्यवसाय तथा नौकरी के लिए चले गए थे वे छत्तीसगढ़ वापस आ रहे है।

7. सभी स्टार्टअप द्वारा उपलब्ध रोजगार 712
8. सभी स्टार्टअप का कुल टर्न ओवर (मार्च 19) 97 करोड़
9. छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप में निवेश करने वाले तथा निवेश के इच्छुक निजी क्षेत्र के फण्ड
   (अ) अम्बूजा निवोटिया
   (ब) भारत इनोवेशन फण्ड स इंडियन एंजेल नेटवर्क

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					10. छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप संख्या जिनमे निजी क्षेत्र के फण्ड का निवेश हुआ 11. नीति आयोग द्वारा समर्थित सभी इन्कुबेटरों में सर्वाधिक स्टार्टअप संकलित कर प्रथम स्थान प्राप्त		
8.	नागरिक संबंध केन्द्र योजना	शासन की जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन की हितग्राहियों की प्रतिक्रिया के आधार पर समीक्षा	92700	एक कॉल सेंटर की स्थापना एवं समस्त हितग्राहियों के समेकित डेटाबेस का विकास कर शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का 'फीडबैक' लेना	सफलतापूर्वक 12 लाख नागरिकों को संपर्क किया गया एवं उनकी प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई।	63000	
9.	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य के प्रमुख अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा	19470	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्राजेक्ट्स की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मॉनिटरिंग टीम की सीापना	केन्द्रीयकृत परियोजना प्रबंधन सिस्टम तैयार करने हेतु विभागों में उनके यहां वर्तमान में जैसी प्रक्रिया संचालित है, और उस प्रक्रिया में वांछित बदलाव के आधार पर अनुमोदित रिर्पाट ;AS-IS TO-BE & SRS) उपरोक्त विभागो द्वारा प्रदाय की गई है। 3D दृश्य/समीक्षा परिचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा मनोनित अधिकारियों को Building Information Modelling में कार्य किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है।	7788	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					मेजरमेंट बुक के वेब एप्लीकेशन एवं मोबाईल-एप का निर्माण भी किया गया जा चुका है। उपरोक्त 5 विभागों द्वारा CPMS की प्रमाणित UAT (User Acceptance Test) प्रदाय की जा चुकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ रोड डेव्हलमेंट कार्पोरेशन, अटलनगर विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मनोनित दो-दो परियोजनाओं का CPMS में ऑटोमेशन का कार्य किया जा चुका है, छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ राज्य पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में ऑटोमेशन का कार्य प्रगति पर है। विभागों में संचालित वित्तीय प्रणाली का CPMS के साथ एकीकरण का कार्य पूर्णत: पर है। विभागों में कार्यरत अधिकारियों को एक वर्ष के लिये सॉफ्टवेयर संचालन में सहायता एवं आवश्यक समन्वयन प्रदान करने हेतु 5 सदस्य फेसिलिटी मैनेजमेट सर्विस (FM)का प्रावधान किया जा चुका है। CPMS के तकनीकी संचालन हेतु परियोजना-केंद्र चिप्स में दो सदस्यीय ऑपरेशन सपोर्ट यूनिट (OSU) 3 वर्षो हेतु उपलबध कराये गये हैं।		

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					सिस्टम के सफल संचालन हेतु उपयोगकर्त्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं आवश्यक संबंधित सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी।		
10.	कौशल विकास एवं प्लेसमेंट हेतु अनुदान	आईटी एवं आईटीईस के क्षेत्र में युवाओं का कौशल उन्नयन	51722	आईटी एवं आईटीईस के क्षेत्र में युवाओं का कौशल उन्नयन	उपरोक्त परियोजना तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।	0	
11.	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	322000	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हुत स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	1. वितीय वर्ष 2018-19 में लगभग 175 से अधिक वेबसाइटों एवं एप्लीकेशन जोकि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित एवं संधारित की जाती है उनका सफलतापूर्वक होस्टिंग प्रदान करना 2. वितीय वर्ष 2018-19 के पश्चात लगभग 12 रैक में नवीन 63 सर्वर जोकि डायल 112, भारतनेट एवं स्मार्ट सिटी रायपुर प्रोजेक्ट से संबंधित है, का सफलतापूर्वक स्टेट डेटा सेंटर में विस्थापित किया गया 3. विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हेतु स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना	0	
12.	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	ग्रामों में नागरिकों को ई-गवर्नेंस एवं ई-भुगतान की सेवाएँ प्रदान करना	30000	सामान्य सेवा केन्द्रों का संचालन करना	सामान्य सेवा केन्द्र 2.0 परियोजना अंतर्गत राज्य के 10971 ग्राम पंचायतों में से 10200 ग्राम पंचायतों को परियोजना में सम्मिलित किया जाकर ग्रामीण नागरिको को जनोपयोगी सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	जिला ई-गवर्नेस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	14904	27 जिला ई-गवर्नेस सोसायटी का संचालन करना	जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं G2C सेवाओं की विभिन्न सेवा श्रेणियों में ट्रांजेक्शन की संख्या की रिपोर्ट । सेवाओं की प्रदायगी की गुणवत्ता के स्तर की मानिटरिंग । किसी भी प्रकार के तकनीकी सहायता हेतु हेल्पडेस्क के साथ समन्वय जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु समन्वय तकनीकी अधोसंरचना के आवश्यक रख-रखाव एवं कनेक्टिविटी की समीक्षा एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना	8942	
14.	मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना	विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ एवं उच्च शिक्षित युवाओं की सेवा योजनाओं के निर्माण, समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु प्राप्त करना	63100	40 कार्यालय को फेलोज की सेवाएं देना	43 मुख्यमंत्री सुशासन फेलोज की पदस्थापना कर शासकीय योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन एवं संवर्धन का कार्य किया गया।	63100	
15.	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सर्वाजनिक स्थलों पर नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	2600	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	वाई-फाई सिटी परियोजना के अंतर्गत राज्य के पांच शहरों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, एवं अंबिकापुर) में 19 सार्वजनिक स्थानों में नागरिकों के लिए वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी है।	2600	

निष्पादन बजट वर्ष 2018–19

विभाग– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष– सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	स्वान परियोजना का विस्तारीकरण	स्वान नेटवर्क का विस्तार कर दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों को जोड़ना	20000	योजना का संचालन करना	कुल वीडियो कान्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराये गए विभाग/ कार्यालय – 245 कुल वीडियो सभा आयोजित – 2991 सीजीस्वान के वर्तमान MCU की विडियो कान्फ्रेंसिंग क्षमता को 170 से 500 में अपग्रेड कर लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिप्स को ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संसथान (निमोरा) एवं 146 जनपद पंचायत कार्यालयों के मध्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित किया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत चिन्हित जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मध्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित किया गया । वन विभाग अंतर्गत चिन्हांकित वन मंडल एवं वन संभागीय कार्यालयों के मध्य विडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापित किया गया । महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत चिन्हांकित किशोर न्यायालयों एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों के मध्य विडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापित किया गया । पुलिस मुख्यालय एवं संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना में विडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापित किया गया।	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	संचार क्रांति योजना	राज्य में मोबाईल नेटवर्क का विस्तार एवं मोबाईल के उपयोग को बढ़ावा देना	5200000	45 लाख स्मार्टफोन का नि:शुल्क वितरण करना	29,14,845 स्मार्टफोन का नि:शुल्क वितरण किया गया।	2080000	
18.	विशिष्ट पहचान (आधर) परियोजना	राज्य में आधार योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन करना	12000	राज्य के आधार इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में चिप्स को तथा पंजीयक के रूप में इ.सू.प्रौ. विभाग को कार्य करने हेतु सक्षम करना	विशिष्ट पहचान परियोजना अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण (UIDAI) एवं चिप्स का अनुबंध निष्पादित किया गया है जिसके अनुरूप राज्य की विभिन्न हितग्राही मुलक परियोजनाओं में AUA सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।	0	
19.	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	200000	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	179 ग्राम पंचायतों का एकीकरण SNOC से किया जा चुका है परन्तु स्वीकृति परीक्षण MSI द्वारा किया जाना है ।	0	
20.	वर्चुअल एजुकेशन योजना	राज्य में ई-शिक्षा को बढ़ावा देना	54750	शालाओं में ई-शिक्षा प्रदान करना	यूनिकोड यहां वर्चुअल एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिक्षा पोर्टल ई-विद्या के नाम से विकसित किया गया है। ई-विद्या शिक्षा क्षेत्र में सभी हितधारकों को सभी तरह के समाधान और सेवाएं प्रदान करेगा। यह छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रवेश का एकमात्र Çcnq होगा और शैक्षिक सामग्री, एप्लिकेशन और रिकार्डों के केंद्रीय भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा।	0	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
					वर्चुअल एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत 5 स्कूल मनोनीत कर User Acceptance Testing (UAT) के पूर्व पायलट टेस्ट अगस्त 2018 में एक महीने के लिए किया गया। इसके पश्चात eVidya सॉफ्टवेयर के फीडबैक के लिए चयनित स्कूल शिक्षकों एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार संचालक, SCERT को UAT के लिए प्रभारी अधिकारी एवं यथा आवश्यक सहयोगी के लिए निर्देशित किया गया था किन्तु इस पर आज पर्यंत कार्यवाही अपेक्षित है।		
21.	संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी नवाचार प्रयोगशाला	प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु एक केन्द्र की स्थापना कर इनोवेशन को बढ़ावा देना	10	आई.आई.आई.टी नया रायपुर में प्रयोगशाला की स्थापना हेतु मानव संसाधन उपलबध काराना	इस कार्यालय से प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (छव 663@CEO/CHiPS/ICT/2019 dated 5जी April 2019) एवं मिशन संचालक, समग्र शिक्षा (765/CEO/CHiPS/ICT/2019 दिनांक 18जी April 2019) को eVidya परियोजना के अद्यतन के लिए अनुरोध किया गया था किन्तु आज पर्यंत कार्यवाही अपेक्षित है।	0	
22.	छत्तीसगढ़ स्टेट स्पासियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य हेतु ऑनलाईन बेव जीआईएस प्लेटफार्म श्विकसित करना	8605	विभागों को जीआईएस प्लेटफार्म पर ऑनलाईन प्रदान करना	भारत सरकार से परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन अपेक्षित है।	0	